तथापि, विधुत, गैस व जल आपूर्ति, व्यवसाय, होटल व रेस्तरां; परीवहन भण्डारण तथा संचार; वित्त, बीमा, जमीन-जायदाद तथा व्यवसाय सेवाओं, समुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं के संबंध में रोजगार की वार्षिक वृद्वि पर (3.5% प्रतिवर्ष से अधिक) महत्वपूर्ण थी।

मौजूदा संकेतों के अनूसार रोजगार के अवसरों में विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में, उल्लेखनीय वृद्धि की समभावना कम है, परन्तु उसके साथ ही होटल, रेस्तरां, पर्यटन, सूचना प्रौधोगिकी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों का सृजन हो रहा है।

Job Prospects in New Industries

†*61. SHRI KAPIL SIBAL:††

DR. D. MASTHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been wide changes in the contribution of various sources in the gross domestic product of the country after adopting the policy of globalization and liberalisation;

(b) if so, whether the above changes have resulted in .new job avenues in new industries whereas job opportunities in conventional industries have declined; and

(c) if so, the Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Percentage distribution of Gross Domestic Product (GDP) by economic activity at 1993-94 prices reveals an increasing trend in respect of manufacturing; electricity, gas and water supply; trade, hotel and restaurants; transport storage and communication; financing, insurance, real estate and business services; and community, social and personal services, Decreasing trend has been

† Original notice of the Question was received in Hindi.
†† The question was actually asked on the floor of the House of Shri Kapil Sibal.

observed in respect of agriculture, forestry and fishing, and mining and quarrying.

There has been a steady increase in GDP in recent years after adopting economic reforms.

Estimates of employment and unemployment are obtained from the comprehensive surveys conducted by National Sample Survey Organisation (NSSO). From the last two comprehensive surveys on employment and unemployment conducted by NSSO during 1987-88 and 1993-94 (latest available) a positive annual growth rate of employment has been observed in all the sectors of the economy. However, the annual growth rate of employment was significant (more than 3.5 per cent p.a.) in respect of electricity, gas and water supply; trade, hotel and. restaurants; transport, storage and communication; financing, insurance, real estate and business services; and community, social and personal services.

As per current trends, employment opportunities particularly in manufacturing sector may not grow significantly but at the same time new opportunities are being created in the services sectors such as hotel and restaurants, tourism and information technology.

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, this is a very serious issue because it impacts on the avenues of employment, pursuant to the adoption. of liberalisation and globalisation policies by this Government. Sir, if you look at the experience of the OECD nations, among the developed countries of international community, you will find that in absolute terms, even in those nations where liberalisation has been adopted, even in those nations who have embraced liberalisation, though there are increasing avenues in the service sector, there are decreasing avenues of employment in the agricultural sector and in the manufacturing sector. I am not talking about the experience of the less developed world. I am talking about the experience of the OECD countries; and G-7 countries and the G-8 countries. I may give you an example, and then I will specifically put my question. Sir, in the United States, for example, over a period of 20 years, after the liberalisation policy has been embraced, the average asset holding of the top one per cent of the population is

795,000 dollars, whereas the asset holding of the bottom forty per cent has decreased by 49%; and the asset holding of the top one per cent has increased by 28% ...*(Interruptions)*... one second, I am putting the question,

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, there is an increase in the asset holding of the top one per cent by 28%; and a decrease in the asset holding of the bottom forty per cent by 50%. Now, the question that I ask is, has this Government done any survey, as to the decrease of employment opportunities in the manufacturing and the agricultural sector, because that is where the opportunities lie, and what will be the impact of that in the next 10-20 years; Would the hon. Minister respond to this? Then I will ask my second supplementary.

डा. सत्यनारीयण जटिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि किन क्षेत्रों में वैश्रीकरण और उदारीकरण के कारण रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं। प्रश्न के जवाब में यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बता दिया गिया है कि आर्थिक गतिविधियों से वर्ष 1993-94 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विर्निमाण, विद्युत, गैस तथा जल आपुर्ति, व्यवसाय, होटल एवं रेस्तरां, परीवहन, भंडारण एवं संचार, वित्त, बीमा, जमीन-जायदाद तथा व्यवसाय सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं, की वितरण प्रतिशतता में वृद्धि का रूझान दिखाई दिया है, कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन एवं खनन व उत्खनन में गिरावट का रूझान दिखाई दिया है।

महोदय, निशिचत रूप से किसी भी देश की प्रगति में ये जो कारक है, जिसको हमने, कृषि कहा है, हम जानते है कि विकास जब होता है तो बाकी की जो परंपरागत चीज़ें होती हैं वे जाती है और नयी चीज़े आती है पशु-पालन से कृषि से औधोगिक विकास, यह एक तरह से अंतर्निर्भर हैं और इसलिए इस दिशा में जो कुछ भी किया गया है, ऐग्रीकल्चर के सैक्टर में भी जब यह वैश्रीकरण और उदारीकरण लागू किया गया था सन् 1991 में, उससे पहले भी यह ट्रैंड कृषि में मौजूद था। महोदय, 1978 में जो प्रतिशतता प्राप्त हुई है, वह 72.30 प्रतिशत है। 10 वर्ष बाद 1986 में यह कम होकर कृषि के क्षेत्र में 66.20 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह 1994 में जो कि वैश्रीकरण के बात का फिगर है, यह कम होकर 64.80 प्रतिशत हो गई है उसके बाद 1997 में जो फिगर उपलब्ध है वह 63.81 परसेंट है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैश्रीकरण से पहले भी चूंकि हम प्रगति की दिशा में बढ़ रहे थे, विकास की दिशा में बढ़ रहे थे, इसलिए कृषि के क्षेत्र का यह फिगर नीचे जा रहा था। इसी प्रकार से माईनिंग के सैक्टर की

और मैन्युफैक्चरिंग और बाकी क्षेत्रों की फिगर्स मेरे पास उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य को प्रश्न के उत्तर में मैंने बता दिया है और आप भी जानते हैं कि ऐग्रीकल्चर के सैक्टर में, माईनिंग के सैक्टर में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, यह कमी आई है। चूंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, प्रकृतिक पदार्थ हैं, इसलिए खनिज संपदा और उत्खनन के क्षेत्र में कमी होती जाएगी और जिन क्षेत्रों बढ़ोत्तरी में हो रही है, उनका भी वर्णन आपके सामने आया हैं। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि वे किस क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से जानकारी चाहते हैं?

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, this is in the context of the overall liberalisation and globalisation issue. The point is that the largest employment is in the unorganised sector, in the agricultural sector. If you admit that there is a decreasing share of the agricultural sector qua the GDP, that the employment is decreasing in the agricultural sector and that there are not enough opportunities in other sectors for absorbing that employment, you are going to have a time bomb on you hands. This is the point that I want to put before this hon. House. For absorption in other sectors you need 100 per cent literacy in the country. The levels of literacy in this country are such that the surplus produced in the agricultural sector will not be allowed to be absorbed because they do not have that level of literacy to get absorbed. So, you are going to have a *time bomb* in ten or twenty years from now.

The question that I ask is; are you going to review the liberalisation and globalisation policies in the context of the impending *time bomb.* This is the question I ask.

डा. श्री सत्यनारीयण जटिया: चूंकि यह संक्रमण काल है, ट्रांजीशन पीरियड है, इसलिए इस पीरियड में ... (**व्यवधान**)

SHRI KAPIL SIBAL: You are also in a transitional period.

DR. SATYA NARAYAN JATIYA: Everybody is in a transitional period,

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Sibal, you are also in a transitional period.

DR. SATYA NARAYAN JATIYA: Everybody is in a transitional period. But our country is advancing.

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने रोजगार के बारे में चिंता प्रकट की है कि इस संक्रमण अवधि में जब हम एक नीति से दूसरी नीति की ओर जा रहे है या एक पालिसी को ऐडॉप्ट करने के बाद उसके जो परिणाम आ रहे हैं, उनका प्रभाव रोजगार पर क्या होने वाला है। निश्चित रूप से जो भी कमी हो रही है किसी क्षेत्र में, वह इसलिए हो रही है क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में कारेस्पांडिंग वृद्धि हो रही है। आप जानते हैं कि देश में जो सम्बल हमारे पास है वह प्रायः 36 करोड़ का सम्बल है और उसमें भी जो रोजगार के अवसर सृजन हो रहे हैं और जो रोजगार के अवसर की मांग है वह 2.5 प्रतिशत है जितना रोजगार चाहिए उतना हम दे पा रहे हैं नए क्षेत्रों में भी और उसके कारण ही 2.5 की प्रतीशतता पर प्रायः-प्रायः संतुलन स्थापित हुआ है आज की स्थिति में।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: फिर यह इतनी बेरोजगारी क्यों फैली हैं?

श्री मोहम्मद सलीम: मंत्री जी आपने जहां से खत्म किया है मैं वहां से सवाल पूछना चाहता हूं कि जितना आवश्यक है या जितनी मांग है बेरोजगारों को नौकरी के लिए या काम के लिए उतना आप दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जब यह एल.पी.जी. शुरू हुई या लिबरेलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ उस समय की नई नीति 1991 में कहा गया था कि ईयर 2000 तक नियर्ली फुल एम्प्लोयमेंट हो जाएगा। वह भी पूरा होगा और बैकलॉग भी होगा। उसी के कारण साल में एक करोड़ बेरोज़गारों को काम देने की आपकी बात 90 के दशक में हमनें सुनाई। आपके जो बैकलॉग थे वे और जो जॉब्स के लिए मार्केट में नए एंट्रेंस आएंगे उनको भी आप दे देंगे। अभी आपका कहना है कि जितनी मांग हो रही है उतना हम दे रहे हैं, जबकि सवाल यह था कि नई इण्डस्ट्रीज में चुंकि सिनेरियो चेंज हो गया है तो जॉब्स क्रिएशन कितने हो रहे हैं, अपार्च्युनिटी कितनी बढ़ रही है? मंत्री जी कह रहे हैं कि जितनी मांग है उतनी पूरी हो रही है और यह भी कहा कि मेन्युफेक्चरिंग सैक्टर में, ट्रेडिशनली माईनिंग सेक्टर में और एग्रीकल्चर सैक्टर में कम हो रहा है क्योंकि अदर्स में बढ़ रहा हैं। इसका मतलब है कि आपने ऐसे स्वर्ग की स्थिति बनाई है जहां और बेरोज़गारों को कोई परेशानी नहीं है यह आप सदन में कह रहे हैं, सदन को सूचित कर रहे हैं अपने आंकड़े के मुताबिक। आपको क्या यह मालूम है कि रिसेंटली एक सर्वे किया गया था, वह हमने नहीं, कोई पौलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने नहीं और न किसी गवर्नमेंट ने ही किया है, यह फॉर्मर चीफ आफ दि ब्यूरो आफ दि सेटेटिस्टिक्स दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरे देश में किया था। यह कहा था कि यह जो इंवेस्टमेंट एंड जो एम्पलोयमेंट रेशो है वह बड़ा गड़बड़ा गया है दस साल में। यह सवाल यहां पर आया था। केपिटल इनवेस्टेड एंड एम्पलोयमेंट जेनिरेटेड वह गड़बड़ हो गया। केपिटल इंटेंसिव जा रहा है, लेबर इंटेंसिव नहीं हो रहा है। सौ करोड़ से ज्यादा लागत वाली इण्डस्ट्रीज थी ट्रेडिशनली,

और जो नई बन रही है या जिन्हें आप ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं उसमें एन्युअली 10 परसेंट डिक्लाइन हो रही है जॉब अपार्च्युनिटी। सिर्फ जो नीचे के क्षेत्र के हैं, दस करोड़ से कम लागत की जो कम्पनियां हैं, कारखाने हैं उसमें फिर भी कुछ एम्प्लोयमेंट जेनिरेट हो रहा है। आपकी पॉलिसी से एल.पी.जी. की पॉलिसी से, जो छोटे क्षेत्र की और मध्यम क्षेत्र की और मध्य क्षेत्र के कारखाने हैं, जो कंपनियां हैं वहां आहिस्ता-आहिस्ता कम्पटीशन में ही वे खो जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है और बड़ी कम्पनियां आ रही हैं तो यह जो कंट्रास्ट है इसको आप लेबर मिनिस्ट्री से कैसे मिलाएंगे जबकि ऊपर जो नई कम्पनीज़ आ रही हैं विद दि मेजर इंवेस्टमेंट वहां जॉब अपोर्च्युनिटी घटती जा रही है, नए क्रिएट नहीं हो रहे हैं ओवर ऑल, क्या आप इससे अवेयर हैं? यह आपकी सरकार के पास भी भेजा गया था, अखबार में भी आया है। तो इस हालत से निबटने के लिए आप क्या रास्ता दिखा रहे हैं? आप कब तक नियरली फुल एम्पलोयमेंट देंगे? और अगर दो हजार तक नहीं किया तो कब तक करने जा रहे हैं?

श्री सत्यनारायण जटिया: जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और वह जो संदर्भ कर रहे हैं मोंटेक सिंह अहलुवालिया कमेटी के बारे में, तो कमेटी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो सरकार उस पर निर्णय करेगी और निर्णय करने के बाद जो नीति बनेगी उसको क्रियान्वित करने का काम हर वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो आज रोजगार की स्थिति है उस रोजगार की स्थिति में भी जो लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं जिनको काम नहीं है वे 80 लाख लोग हैं। 80 लाख लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं है।...(**व्यवधान**)

श्री कपिल सिब्बल: यह आंकड़े आप कहां से ले आए हैं? ...(**व्यवधान**)

श्री सत्यनारायण जटिया: उसके साथ ही साथ जिनको पूरा रोजगार नहीं है ऐसे दो करोड़ तीस लाख लोग हैं जिनको पूरा रोजगार नहीं है। हम जब रोजगार की बात करते हैं तो साल में अधिकांश दिन यानी 183 दिन जिनको रोजगार मिल रहा है उसको रोजगार मिला हुआ है, ऐसी मान्यता हैं। इस दृष्टी से जो कुछ भी हो रहा है और जैसा कि माननीय सदस्य को चिंता है-हम जानते हैं कि ऑर्गनाइज्ड सैक्टर में-वह भी पब्लिक सैक्टर के जो सारे रोज़गार थे, वह कम हो रहे हैं और निजी सैक्टर में रोजगार बढ़ रहे हैं। एक समय था जब इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए उसका विकास करने के लिए हमें अधिक से अधिक नये पब्लिक सैक्टर्स का निर्माण करना जरूरी था लेकिन आज वह बात निजीकरण की ओर जा रही है। निजीकरण की ओर जाने के कारण भी रोज़गार के

अवसर पब्लिक सैक्टर से प्राइवेट सैक्टर की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार से रोज़गार के अवसर जहां एक ओर कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ रहे है, ऐसा आपको प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो गया होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने दो उत्तरों में बार-बार यह बात कही है कि यह संक्रमण काल है और अगर कृषि उद्योग में रोज़गार घट रहा है तो कॉरसपाँडिंगली दूसरे उद्योग में रोज़गार बढ़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या उन्हीं लोगों को रोज़गार कॉरसपाँडिंगली दूसरे क्षेत्र में मिल रहा है जिनका रोज़गार घट रहा है वे अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वे सड़क पर आ गये हैं और जिनको नया रोज़गार मिल रहा है, वे बिल्कुल नये लोग हैं। इसलिए आपके कागज़ों में औसत भले ही ठीक बैठ रहा हो लेकिन वास्तविकता में जिनके लिए रोज़गार घट रहा है, उनको रोज़गार का अवसर नहीं मिल रहा , नये लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा है और जिन नये लोगों को रोज़गार का अवसर मिल रहा है वहां भी पूंजी विनिवेश और रोज़गार का अवसर- इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। कर्णाटक में आई.टी. सैक्टर में 27 हजार करोड़ का विनिवेश हुआ और इम्पिलेमेंट केवल 2700 लोगों का हुआ। यानी 10 करोड़ पर एक व्यक्ति। इस लिए आप केवल अपने कागज़ों में ग्राफ में औसत ठीक बैठाकर सदन को अश्वस्त कर दें कि कॉरसपाँडिंग्ली बराबर रोज़गार मिल रहा है, यह सही नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि जिनके रोज़गार के अवसर समाप्त हो गये हैं, क्या उनके लिए नये रोज़गार की व्यवस्था आप कर रहे हैं या नहीं?

डा. सत्यनारायण जटिया: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, निश्रित रूप से उस संबंध में हम चिंतित हैं। जो मोंटेक सिंह अहलुवालिया कमेटी बनायी गयी है, निर्माण के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए है। क्योंकि एक करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोज़गार देना है इसलिए जिनके पास स्किल नहीं है, जिनके पास श्रम कौशल नहीं है, ऐसे लोगों को रोज़गार देने के बारे में विचार करने के लिए तथा एक करोड़ लोगों को रोज़गार देने के संबंध में यह बात आयी है। साथ ही साथ सरकार की जो ग्रामीन रोज़गार की योजना है, शहरी रोज़गार की योजना है, उसमें भी रोज़गार देने के लिए काम हो रहा है। यह बात जरूर है कि कृषि में अनइम्पलॉयमेंट का प्राब्लम बना हुआ हैं, रोजगार देने का प्रॉब्लम बना हुआ है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम चलाकर कृषि क्षेत्र के लोगों को रोज़गार देने की दृष्टि से अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा है। इस आधार पर जहां रोज़गार कम हो रहे हैं, उस बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हमारा जो श्रम बल है उसमें से 33 करोड़ का श्रम बल असंगठित क्षेत्र में है। उस असंगठित क्षेत्र के श्रम कौशल को यदि हम कौशल दे सकें, उसमें स्किलनैस दे सकें तो निश्रित रूप से हम दुनिया के सबसे बड़े श्रम शक्ति

के देश हो जाएंगे। वैश्रीकरण का कॉन्सैप्ट बन गया है कि पूंजी का सारी दुनिया में आवगमन प्रतिबंध रहित हो जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि दुनिया में वैश्रीकरण के लिए श्रम कौशल का प्रतिबंध भी घटने का काम होता रहना चाहिए – यह भी वैश्रीकरण के कॉन्सैप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वक्त आशंका करना की जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको रोजगार के अवसर नही मिलेंगे, ठीक नही है।

प्रो॰ रामगोपल यादव : चेयरमैन साहब, देश जब आजाद हुआ था तो खेती का जी॰डी॰ पी॰ में जो हिस्सा था, वह पचास फीसदी था। इकॉनामिक सर्वे के हिसाब से पिछले साल जी॰ डी॰ पी॰ में ऐग्रीकल्वर का शेयर 24.6 परसेंट हो गया है। उस वक्त भी खेती पर 70 परसेंट से 72 परसेंट तक लोग निर्भर थे और आज भी इतने ही लोग खेती पर निर्भर हैं। एक वक्त था जब इस देश की पूरी सम्पति में आधा हिस्सा खेती पर निर्भर रहने वालों का था, आज वह शेयर 24 परसेंट रह गया है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह करोड़ों लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, उनके लिए क्या विशेष योजना है? केवल उसके जरिए काम नहीं चल सकता है कि कुछ बड़ी कम्पनियां लगा दी जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। सुषमा जी ने कहा कि सारे लोग लगभग गरीबी की रेखा के नीचे चले गये हैं। वे 70 परसेंट लोग हैं, जिनकी सम्पति केवल 24 परसेंट रह गयी है। जब देश आजाद हुआ था तब वह पचास परसेंट थी, इसके लिए आपके पास क्या योजना है?

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जो परिकल्पना है, तो आज की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें गरीबी रेखा के नीचे 36 प्रतिशत लोग हैं। जब हम गरीबी रेखा की बात करते हैं तो उसकी इनकम के बारे में, प्रति परिवार की जो वर्षिक आय है और हमने परिवार रूप जो माना है, वह पांच यूनिट का माना है । उसमें जो एक व्यक्ति कमाने वाला है, उसको वर्ष भर में जो आय होने वाली है, वह 21600 रूपए होनी चाहिए यानि यदि 1800 रूपए प्रति माह उसकी आय रहे तो वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है इसके साथ-साथ एक प्रश्न और जो हमारे सामने है, वह जनसंख्या की वृद्धि की दर का है और उसके कारण रोजगार की जो परिस्थितियां हैं, उन रोजगार परिस्थितियों का संतुलन बिगाड़ने के लिए यह जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में अगर आज हम यह देखें की 14 साल से ऊपर के लोगों के लिए कितना रोजगार होना चाहिए, तो 1985 की जनसंख्या के हिसाब से वह आज हमको नजर आ रहा है। आने वाले वर्षों में जनसंख्या की दर जिस तरह से हमारी होगी और जनसंख्या के साथ-साथ

रोज़गार की दर जिस प्रकार से हमारी होगी, आज स्थिति यह है कि जनसंख्या की दर और रोज़गार की दर को अगर हम ईक्वेट करें तो निश्रि त रूप से हम पाएंगे कि रोज़गार के जो अवसर होने चाहिए, उनसे ज्यादा की आज देश को जरूरत है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ रामगोपल यादव : उनका रोज़गार दफ्तर में नाम नही लिखा है।

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो सड़क निर्माण का काम है, उस सड़क निर्माण के काम में भी, हाऊसिंग के काम में भी बड़ी संख्या में लोग लगेंगे और उसके साथ-साथ सिंचाई और बाकी के विकास के कामों में सड़कों का इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी लोग लगेंगे इसलिए हम उमीद करते है कि यह जो रोज़गार की समस्या होने वाली है, उससे हम निजात पा सकेंगे

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The Hon. Minister has pointed out that with the movement of the capital, there should be free, uninterrupted, movement of the labour forces as an object of globalisation. But, unfortunately, it is not taking place, Mr. Minister. That may be an ideal order. The industrialised countries are insisting on the movement of capital and uninterrupted, easy, mobility of the capital. But when the question of movement of work force comes, ihen they are raising the non-tariff protection against such movement; particularly, the visa restriction in one of the important leading countries is a glaring example. The second point you have referred to is also not actually coming. Theoretically, may be, you can compensate by creating more employment in the rural development sector to the extent the employment opportunities are getting reduced in agriculture. But, unfortunately, if you look at the actual allocation and spending, noMllocation at the Budget Estimate stage, for three consecutive years, there are differences between the Budget Estimates and the Actual Expenditure, shown as the Revised Estimates. In all important anti-poverty programmes, the Actual lixpenditure ha» been less than the budget Estimate. As a consequence, to the extent of an average of Rs. 1.0,000 crores, there is less expenditure in the Central Plan.

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया: निश्चित रूप से यह बजट और वित्त प्रश्न रखा है जो कि हम माननीय सदस्य से उम्मीद कर सकते थे। लेकिन प्रश्न है रोज़गार का और रोजगार के अवसरों का तो जिस प्रकार से एग्रीकल्चर के माइनिंग के क्षेत्र में हमारे रोज़गार के अवसर कम होते चले

जा रहे हैं किंतु मैन्युफैक्चरिंग मे निश्चित रूप से ये बढ़े हैं, यदि हम कम्पेयर करें 1994 से तो उससे हमको थोड़ा सा ट्रेंड पता लग जाएगा। 1978 से यदि हम कम्पेयर करें तो यह पता लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जो 9.80 परसेंट था वह बढ़कर 10.38 परसेंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You have to give the absolute numbers. Percentage does not help.

DR. SATYA NARAYAN JATIYA: I have them here, आप यदि चाहेंगे तो उसका विस्तृत ब्यौरा मेरे पास है। इसलिए चूंकि परसेंटेज में, जी॰डी॰पी॰ जब कैलकुलेट किया जाता है तो एक साल से दूसरे साल की तुलना में उसकी आनुपातिक वृद्धि किस प्रकार से हुई है, उस अनुपातिक वृद्धि को तुलना करके हम देखते हैं। एक समय था जब यह आनुपातिक वृद्धि कम होती चली जा रही थी और फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमने देखा कि यह परिवर्तन का क्रम रिवर्स हो गया और हमने देखा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक जो रोज़गार की दर थी, वह 2.7 प्रतिशत थी। छठी पंचवर्षीय योजना में यह 2.7 प्रतिशत थी। सतवीं पंचवर्षीय योजना में यह कम होकर 1.7 प्रतिशत हो गई और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद उसका 2.3 परसेंट का बढ़ता हुआ ट्रेंड हमें दिखाई दिया। निश्रित रूप से नौंवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि 2.5 प्रतिशत तक रोजगार की दर को बढ़ाना है और किस प्रकार से निरंतर रोज़गार की दर को बढ़ाया जा सकता है? सरकार का इस प्रकार का प्रयास है?

MR. CHAIRMAN: Now, the Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Reciprocation of India's gesture

*62. SHRI DINA NATH MISHRA: Wi'l the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state in the background of India's tradition of'honouring important heads of various States by providing the forum to address Members of both the Houses of Parliament, what are the names L? countries which have given similar opportunities to the President or the' Prime Minister of India?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): As there is no specification of the period for